उत्तर प्रदेश में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

3219. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गैर पार-परिक ऊर्ज स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए क्या प्रयास किये गये हैं, और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में उपरोक्त कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा लघु जल विद्युत बायोमास आदि जैसी पारम्परिक उर्जा स्रोतों पर आधारित लगभग 25 मेगावाट की कुल क्षमता की कई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार निधतन नहीं किए गए हैं। तथापि योजना आयोग ने राज्य योजना के अंतर्गत आठवीं योजना अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र हेतु 25 करोड़ रुपये के परिव्यय की अनुशंसा की है।

POPULARIZATION OF NON-CONVENTIONAL ENERGY BASED EQUIPMENTS AMONG FARMERS

3220. **SHRI BHUPINDER SINGH MANN** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that country faces energy problem at the peak load hours;

(b) whether Government have any plants to encourage farmers to install equipments of non-conventional nature, such as solar equipments to run their tube-wells and meet their domestic need of electricity;

(c) if so, in what way; and

(d) whether any subsidy is proposed in this regard to encourage the farmers of country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Ministry of Non-Conventional Energy Sources is implementing solar photovoltaic, wind and biomass gasifier programmes for providing systems for lighting, water pumping and for other small power applications. Under the solar photovoltaic programme, two separate schemes i.e. specially oriented scheme and market oriented scheme have been introduced. The socially oriented scheme is mainly for difficult and economically backward areas and for certain categories of beneficiaries in other areas. The scheme provides for government subsidy for 50 per cent of ex-works cost of the systems. The subsidy for solar lanterns is, however, fixed at Rs. 2000 each. The scheme is implemented through State nodal agencies. The market oriented scheme is implemented through the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA). Under this scheme, soft loan assistance is available to individuals as well as commercial organisations for the purchase of solar photovoltaic systems.

A special project for deployment of 1000 solar photovoltaic water pumping systems during 1993-94 for agriculture and related user has been undertaken. The project is being implemented through IREDA and it involves a package of subsidy and loan to the user of the system. All categories of individual farmers, non-governmental organisations, institutions, Co-operatives and corporate bodies are eligible for financial assistance under this project.

Under the water pumping windmill programme, a subsidy of Rs. 22,500 and

Rs. 12,500 is being provided to the user for the installations of gear type and improved 12 PU 500 type wind pumps, respectively.

Under the Biomass gasifier programme, a subsidy of Rs. 12,500 for 5 HP and Rs. 17,000 for 10 HP gasifier powered water pumping system is being provided.

A scheme for rural electrification using biomass gasifier technology has also been launched. Under the scheme subsidy for 75 per cent of the cost of the gasifier system is available.

अनटेप्ड पोटेन्शियल

3221. **श्री राम जेठमलानी** :—क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 1993 को इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित "अनटेप्ड पोटेन्शियल" नामक शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि देश में ऐसे कई उद्योग चलाए जा रहे हैं जहां विद्यमान तकनीकी में कुल परिवर्तन करके विद्युत का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संभावनाओं की प्रामाणिकता की जांच की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि यह संभावनाएं तथ्यों पर आधारित हैं तो क्या सरकार ऐसे उद्योगों को इस दिशा में प्रगति करने के लिए प्रेरक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने बायोमास आधारित सह-उत्पादन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को तैयार करने के कार्य में सहायता देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था । चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन के संबंध में इस कार्यबल की सिफारिशों पर हाल ही में हुई एक राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया । राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को इन सिफारिशों की विस्तृत जांच पडताल करने के बाद शुरू किए जाने की संभावना है । विद्युत मंत्रालय ने भी उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोरसायन आदि जैसे उद्योगों में अतिरिक्त संभाव्यता का आकलन करने और उसका विदोहन करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाने हेतु एक कार्यबल का गठन किया है ।

FOREIGN PROPOSALS REGARDING USE OF OCEANIC ENERGY

3222. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

DR. MURLI MANOHAR JOSHI :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of Indian and Foreign proposals received by Government during the last three years regarding use of oceanic energy;

(b) the number of proposals approved together with the amount of investment;

(c) the number of projects actually installed and operating during the same period; and

(d) the quantity of energy generated or likely to be generated by the project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DE-